तीन साल में जनजाति के विकास पर 3200 करोड़ रु. का प्रावधान किया- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस पर कहा कि समाज के महापुरुषों के बलिदान को सम्मान देना सभी का दायित्व है

जयपुर, 15 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनजातीय समाज ने देश की संस्कृति, परम्परा और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदियों तक संघर्ष किया है। इस समाज के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और महापुरुषों के बलिदान को सम्मान देना हम सभी का दायित्व है। राज्य सरकार



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जनजातीय गौरव दिवस पर जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों एवं युवाओं से संवाद किया।

- **संवाद के दौरान जनजातीय अंचल से आये अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने उदयपुर लैक्रोस एकेडमी सहित प्रदेश में दी जा रही खेल सुविधाओं के लिये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया।**

वंचितों को वरीयता देते हुए जनजातीय समाज के शैक्षिणक, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

रविवार को जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सम्बोधन सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों से संवाद भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने तीन वर्षों में जनजातीय समुदाय के विकास के लिए लगभग 3 हजार 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसी क्रम में 10 आश्रम छात्रावास, 3 आवासीय विद्यालय, एक नया खेल छात्रावास और 250 नए मां-बाड़ी केन्द्र खोले गए हैं। पीएम-जनमन योजना के तहत बारां जिले के सहरिया क्षेत्र में 15 हजार 233 आवासों, 23 सम्पर्क सड़कों, 15 नए बहुद्देश्यीय केन्द्रों का निर्माण और 51 वन-धन केन्द्र गठित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय किसानों को सशक्त बनाने के लिए निशुल्क संकर मक्का बीज मिनी किट तथा हाइब्रिड सब्जी बीज मिनी किट उपलब्ध करवाए गए हैं। इसी प्रकार पीएम कुसुम योजना में 8 लाख से अधिक निशुल्क सोलर पम्प स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं ने खेलों के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय देते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया है। लैक्रोस में प्रदेश के जनजातीय खिलाड़ियों ने वर्ष 2024 में समरकंद एशियन चैम्पियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। इस वर्ष रियाद एशियन लैक्रोस गेम्स में पुरुष एवं महिला, दोनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक हासिल किए गए। इसी प्रकार मलेशिया में आयोजित दक्षिण-पूर्व एशियाई लैक्रोस चैम्पियनशिप-2026 में कांस्य पदक प्राप्त किया।

संवाद के दौरान जनजातीय अंचल से आए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने उदयपुर की लैक्रोस अकैडमी सहित प्रदेश में दी जा रही खेल सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

मृत्युदंड पर रोकः यू.एन. में प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया भारत ने

नई दिल्ली, 15 नवंबर। भारत ने युनाइटेड नेशन्स जनरल असैम्बली (यूएनजीए) में मृत्युदंड पर रोक लगाने की मांग करने वाले प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। इस प्रस्ताव में सभी देशों से मृत्युदंड के इस्तेमाल पर रोक लगाने और इसे समाप्त करने की दिशा

- **प्रस्ताव के पक्ष में 133 देशों ने और विरोध में 33 देशों ने मतदान किया।**

में कदम उठाने की अपील की गई थी। शुक्रवार को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के बाद यह प्रस्ताव पारित हो गया।मैक्सिको की ओर से पेश किए गए मृत्युदंड के इस्तेमाल पर रोक प्रस्ताव के पक्ष में 133 देशों ने मतदान किया, जबकि 33 देशों ने इसके विरोध में वोट दिया। वहीं, 16 देश मतदान से अनुपस्थित रहे। बहरीन, चीन, मिस्त्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका सहित भारत ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया।

प्रस्ताव में मृत्युदंड के लगातार इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई गई। साथ ही सभी देशों के इस अधिकार को दोहराया गया कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपनी कानूनी व्यवस्था और उचित दंड तय कर सकते हैं। प्रस्ताव में सभी देशों से मृत्युदंड पर रोक लगाने का आग्रह किया गया, ताकि भविष्य में इसे पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इसके अलावा, जिन देशों ने मृत्युदंड खत्म कर दिया है, उनसे इसे दोबारा लागू नहीं करने की अपील की गई।

रहमान गुल बलूच लिबरेशन आर्मी का कमांडर -इन -चीफ बना

रहमान पहले पाकिस्तान सेना में कैप्टन था और बगावत करके बीएलए में शामिल हुआ था

- **रहमान गुल बीएलए की मजीद ब्रिगेड का कमांडर रह चुका है। यह संगठन की प्रमुख ब्रिगेड है और आत्मघाती हमलों के लिये जिम्मेदार मानी जाती है।**

क्वेटा, 15 नवंबर। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय प्रतिबंधित संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने अपने शीर्ष नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है। संगठन ने वरिष्ठ कमांडर रहमान गुल उर्फ मुरीद को नया कमांडर-इन-चीफ बनाया है। इस फैसले के साथ ही संगठन की कमान अब एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में आ गई है, जो पहले पाकिस्तान की सेना में कैप्टन के पद पर रह चुका है।

द डॉन अखबार के मुताबिक, वह पहले पाकिस्तान सेना में कैप्टन के पद पर कार्यरत था। बाद में उसने सेना छोड़कर बगावत की और बीएलए में शामिल हो गया। संगठन में शामिल होने के बाद उसने कई अहम जिम्मेदारियां संभालीं और धीरे-धीरे शीर्ष नेतृत्व में अपनी जगह बनाई।

रहमान गुल इससे पहले बीएलए की वरिष्ठ कमांड परिषद का सदस्य था। इसके अलावा वह संगठन की मजीद ब्रिगेड का कमांडर भी रह चुका है। मजीद ब्रिगेड को संगठन की प्रमुख और आत्मघाती हमलों के लिए जिम्मेदार इकाइयों में गिना जाता है। संगठन ने अपने बयान में कहा है कि रहमान गुल को महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का लंबा अनुभव है।

बीएलए में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया नवंबर की शुरुआत में शुरू हुई थी। संगठन ने 3 नवंबर को घोषणा की थी कि बशीर जेब बलोच अब कमांडर-इन-चीफ के पद पर नहीं रहेंगे। इसके बाद संगठन के प्रशासनिक, सैन्य और नीतिगत फैसलों की जिम्मेदारी वरिष्ठ कमांड परिषद को सौंप दी गयी थी। अब रहमान गुल की नियुक्ति के साथ संगठन को नया प्रमुख मिल गया है।

बशीर जेब बलोच दिसंबर 2018 में असलम बलोच की मौत के बाद संगठन के प्रमुख बने थे। असलम बलोच की अफगानिस्तान में आत्मघाती हमले में मौत हुई थी। इसके बाद बशीर जेब ने संगठन की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में बीएलए ने पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठानों, सुरक्षा बलों और चीनी हितों को निशाना बनाकर कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली थी।

बीएलए ने वर्ष 2018 में कराची स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद 2019 में ग्वादर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल और 2020 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले में भी संगठन का नाम सामने आया था। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण की घटना की जिम्मेदारी भी बीएलए ने ली थी।

आरबीआई ने डिजिटल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सकेगा। साथ ही भुगतान प्रणाली से जुड़े संभावित खतरों पर नजर रखना आसान होगा।

आरबीआई के नए दिशा-निर्देश गैर-बैंकिंग भुगतान प्रणाली चलाने वाली कंपनियों पर लागू होंगे। इन नियमों में साइबर हमलों से बचाव और डिजिटल लेन-देन को सुरक्षित रखने के उपाय बताए गए हैं। इनके दायरे में कई संस्थाएं आएंगी। इनमें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), कार्ड से भुगतान की प्रणाली चलाने वाली कंपनियां, अलग-अलग भुगतान सेवाओं को जोड़ने वाली कंपनियां और पहले से पैसे जमा करके इस्तेमाल किए जाने वाले भुगतान साधन जारी करने वाली कंपनियां (पीपीआई) शामिल हैं।

इसके अलावा, वाइट लेबल एटीएम संचालक (डब्ल्यूएलएओ) भी इन नियमों के दायरे में होंगे। केंद्रीय बैंक ने डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा को लेकर सख्त शर्तें रखी हैं। इनमें सॉफ्टवेयर की सुरक्षा, प्रणाली का ऑडिट और तीसरे पक्ष की सेवाएं देने वाली कंपनियों से जुड़े नियम शामिल हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शिखर अग्रवाल के खिलाफ जांच तेज की

प्रदूषण नियंत्रण मंडल से रिसॉर्ट से जुड़ी मंजूरियों, एनओसी तथा उनमें समय-समय पर किए गए बदलावों का रिकॉर्ड मांगा

जयपुर, 15 नवंबर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आईएएस शिखर अग्रवाल और अन्य के खिलाफ प्रारंभिक जांच तेज कर दी है। जांच के सिलसिले में एसीबी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पत्र लिखकर रिसॉर्ट से जुड़ी मंजूरियों, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और उनमें समय-समय पर किए गए बदलावों का रिकॉर्ड मांगा है।

एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता के अनुसार एसीबी की जयपुर नगर-प्रथम इकाई ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से संबंधित पत्रावलियां और नोटशीट उपलब्ध कराने को कहा है। इनमें अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच विभिन्न परियोजनाओं को जारी किए गए "कंसैंट टू एस्टेब्लिश" और "कंसैंट टू ऑपरेट" सहित अन्य एनओसी का पूरा रिकॉर्ड शामिल है। एजेंसी ने यह भी जानकारी मांगी है कि स्वीकृतियां जारी करते समय

- **एसीबी डीजी गोविन्द गुप्ता के अनुसार लैंड कन्वर्जन और फॉरेस्ट एनओसी से जुड़ी शर्तों में यदि कोई बदलाव हुआ है तो उसके लिये सक्षम स्तर से मिली मंजूरी, संबंधित पत्रावलियां और नोटशीट उपलब्ध कराने के लिये कहा है।**

निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का कितना पालन किया गया।

इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों की भूमिका, प्रकरणों के निस्तारण और स्वीकृति प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज भी तलब किए गए हैं।

एसीबी ने इस अवधि में स्वीकृतियों के लिए निर्धारित चेकलिस्ट में किए गए बदलावों का विवरण और उनके पीछे का औचित्य भी मांगा है।

लैंड कन्वर्जन और फॉरेस्ट एनओसी से जुड़ी शर्तों में यदि कोई बदलाव किया गया है तो उसके लिए सक्षम स्तर से मिली मंजूरी, संबंधित पत्रावलियां और नोटशीट भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। जांच एजेंसी ने नाहरगढ़ इको सैंसिटिव ज़ोन से जुड़े दस्तावेज भी तलब किए हैं। इसमें 8 मार्च 2019 को जारी अधिसूचना और ज़ोनल मास्टर प्लान में बाद में किए गए किसी भी बदलाव का रिकॉर्ड शामिल है। एसीबी ने बदलाव के कारण, उन्हें मंजूरी देने वाले अधिकारियों और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगी है।

एसीबी इन दस्तावेजों के आधार पर स्वीकृतियां जारी करने की प्रक्रिया, नियमों और शर्तों में किए गए बदलावों तथा संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच करेगी।

हजार से अधिक जवानों को छत्तीसगढ़ से मणिपुर भेजा

नई दिल्ली, 15 नवंबर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी अभियान क्षेत्र से हजार से ज्यादा जवानों वाली एक बटालियन को हटा लिया है। इस बटालियन को छत्तीसगढ़ से हटाकर मणिपुर भेजा गया है, ताकि वहां जारी जातीय हिंसा के बीच सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मार्च में केंद्र सरकार ने देश में

- **सी.आर.पी.एफ. के ये जवान छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी अभियान का हिस्सा थे।**

सशस्त्र माओवाद के खत्म होने की घोषणा की थी। इसके बाद से किसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीआरपीएफ) की पूरी बटालियन को नक्सल-विरोधी क्षेत्र से वापस बुलाने का यह पहला मामला है।

सीआरपीएफ मुख्यालय ने छत्तीसगढ़ से एक जनरल ड्यूटी बटालियन को वापस बुलाने और उसे मणिपुर भेजने का आदेश दिया है। मणिपुर में पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से जातीय हिंसा चल रही है।

बंद पड़ी ज्वेलरी फैक्ट्री का स्ट्रॉन्ग रुम तोड़कर कीमती गहनों की चोरी

सीतापुरा में यह फैक्ट्री 14 माह से बंद थी तथा 6 माह से गार्ड भी छुट्टी पर था

जयपुर, 15 नवंबर। सांगानेर सदर थाना क्षेत्र के सीतापुरा स्थित एक बंद ज्वेलरी फैक्ट्री में बदमाशों ने सेंध लगाकर स्ट्रॉन्ग रूम से कीमती गहने और अन्य सामान चोरी कर लिया। बदमाशों ने स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार काटकर उसमें बड़ा छेद किया और अंदर रखे सामान पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के दौरान फैक्ट्री का सुरक्षा गार्ड छुट्टी पर था। पीड़ित ज्वेलर पार्टनर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जांच अधिकारी एसआई धर्मवीर ने बताया कि श्याम नगर निवासी अजय शंकर खंडेलवाल (62) ने मामला दर्ज करवाया है कि वह शंकर ज्वेल्स कंपनी में पार्टनर हैं। कंपनी की सीतापुरा स्थित फैक्ट्री में कीमती आभूषण और अन्य सामान तैयार किए जाते थे। इनकी सुरक्षा के लिए परिसर में स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया था। गुरुवार को फैक्ट्री में बने स्ट्रॉन्ग रूम की जांच की गई तो

- **अज्ञात बदमाशों ने 6 फीट ऊंचे व 4 फीट चौड़े स्ट्रॉंग रुम में एक -डेढ़ फीट का छेद बनाया और वहां रखे कीमती गहने आदि चुरा कर भाग गए।**

उसमें एक बड़ा छेद मिला। बदमाश इसी रास्ते अंदर घुसे और वहां रखे कीमती गहने व अन्य सामान चोरी कर ले गए। एसआई धर्मवीर ने बताया कि फैक्ट्री सितंबर 2025 में बंद हो गई थी। इसके बाद कंपनी ने फैक्ट्री को लॉक कर वहां एक सुरक्षा गार्ड तैनात किया था। पिछले 6-7 महीने से गार्ड की तबीयत खराब होने के कारण वह भी छुट्टी पर चला गया था। करीब 14 महीने बाद कंपनी के अधिकारियों ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया तो चोरी का पता चला।

जांच के दौरान फैक्ट्री की एक खिड़की का कांच टूटा हुआ मिला और उसकी ग्रिल भी हटाई हुई थी। स्ट्रॉन्ग रूम करीब 6 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा है। बदमाशों ने इसे काटकर करीब 1 से1.6 फीट का छेद बनाया था। फिलहाल चोरी हुए आभूषणों और अन्य सामान की वास्तविक कीमत का पता नहीं चल पाया है। सेल्सटैक्स विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में स्ट्रॉन्ग रूम खोलकर जांच करने के बाद ही चोरी गए सामान का पूरा विवरण सामने आएगा।

स्पेसएक्स ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वीडियो साझा करते हुए लिखा, मेकाजिला ने स्टारशिप को पकड़ लिया है! पूरी टीम को बधाई।

शुक्रवार दोपहर टेक्सास के स्टारबेस से उड़ा 407 फीट ऊंचा रॉकेट। दोनों स्टेज सफलतापूर्वक अलग हुए। ऊपरी स्टेज स्टारशिप ने कक्षा में पहुंचकर 26 एडवांस्ड स्टारलिंक सैटेलाइट तैनात किए और करीब 260-265 किलोमीटर की ऊंचाई पर 14 चक्कर पूरे किए। यह स्पेसएक्स का 15वां फुल-स्केल स्टारशिप मिशन और कक्षा तक का दूसरा सफल सफर था।

काडमांडू हवाई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तस्करी नेटवर्क का एक प्रमुख सदस्य है। उसके पास से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रमाणपत्र भी बरामद किया गया है।

कांग्रेस ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने पहले ही स्थानीय नेताओं की राय को प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर संगठन के भीतर संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है।

इंडिगो फ्लाइट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गया ताकि लैंडिंग गियर की स्थिति को बाहर से देखा जा सके। इसके बाद, सुबह करीब 9 बजे विमान पुणे एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गया।

पहाड़गंज में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हादसे में कुल आठ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नेतन्याहू की राष्ट्रीय सरकार की अपील को आइज़नकोट ने खारिज किया

पूर्व सेना प्रमुख आइज़नकोट ने कहा कि चुनाव में हारे हुए नेतन्याहू की चालें उन पर काम नहीं करेंगी

तेलअवीब, 15 नवंबर। इज़राइल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूर्व सेना प्रमुख और नई सरकार बनाने की कोशिश में जुटे गादी आइजनकोट से राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने की अपील की है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से पैदा हो रहे खतरे और देश की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए। हालांकि, आइजनकोट ने नेतन्याहू के प्रस्ताव को कुछ ही मिनटों में खारिज कर दिया। आइजनकोट ने कहा कि नेतन्याहू अच्छी तरह जानते हैं कि वह चुनाव हार चुके हैं। उनके मुताबिक, नेतन्याहू ऐसे समय में बातचीत की अपील कर रहे हैं, जब सरकार गठन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच पहले से ही बातचीत चल रही है। उन्होंने साफ किया कि नेतन्याहू की राजनीतिक चालें उन पर काम नहीं करेंगी। इस घटनाक्रम से साफ हो गया है कि इज़रायल में नई सरकार बनाने का रास्ता अभी आसान नहीं है और दोनों नेताओं के बीच मतभेद गहरे बने हुए हैं।

- **नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरु कर रहा है, इसलिये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर इज़रायल में राजनीतिक एकता जरूरी है।**

नेतन्याहू ने शनिवार को जारी वीडियो संदेश में कहा कि ईरान एक बार फिर अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान का लक्ष्य इज़रायल को खत्म करना है और मौका मिलने पर वह उसके खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि इज़रायल को इस खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश में राजनीतिक एकता जरूरी है। नेतन्याहू के मुताबिक, मौजूदा परिस्थितियों में छोटी सरकार या आतंकवाद समर्थक दलों के सहयोग से चलने वाली सरकार देश की सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर पाएगी। उन्होंने सभी बड़ी पार्टियों से मतभेद भुलाकर एक साथ आने की अपील की। हालांकि, आइजनकोट ने उनके इस तर्क को सरकार गठन के प्रयासों में राजनीतिक दखल के तौर पर देखा।

इजराइल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 120 सदस्यीय संसद नेसेट में नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें हासिल हुईं, जबकि आइजनकोट के चार दलों वाले गठबंधन को 48 सीटें मिलीं। अरब दलों ने कुल 19 सीटों पर जीत दर्ज की। चुनाव के बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने सांसदों से पूछा कि वे किस नेता को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में 67 सांसदों ने आइजनकोट का समर्थन किया, जबकि 46 सांसदों ने नेतन्याहू के पक्ष में समर्थन जताया। इसी आधार पर राष्ट्रपति ने आइजनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें इसके लिए 28 दिन का समय दिया गया है। यदि इस अवधि में सरकार नहीं बन पाती है तो उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है।

आइजनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती संसद में बहुमत का समर्थन जुटाना है। उनके गठबंधन के पास फिलहाल 48 सांसद हैं। ऐसे में उनकी रणनीति यह है कि उनके गठबंधन के सभी 48 सांसद सरकार के समर्थन में मतदान करें और नेतन्याहू के 46 सांसद इसके खिलाफ वोट डालें। बाकी 26 सांसद मतदान से दूर रहें तो समर्थन में पड़ने वाले वोट विरोध के मुकाबले अधिक हो सकते हैं। इस रणनीति के तहत आइजनकोट अरब दलों को अपनी सरकार में शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी कोशिश है कि ये दल विश्वास मत के दौरान मतदान में हिस्सा न लें। इससे उन्हें सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन हासिल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, यह रणनीति कितनी सफल होगी, इसका फैसला संसद में होने वाले मतदान से ही होगा।

आज़म खां के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी

लखनऊ, 15 नवंबर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री आजम खां से चार दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम करीब 80 सवाल पूछ चुकी है। हालांकि, रविवार को पूछताछ के दौरान टीम कोई खास बयान दर्ज नहीं कर सकी। चार दिन की रिमांड का सोमवार यानी 16 नवंबर को आखिरी दिन है।

आजम खां के विरुद्ध दर्ज मनी लॉन्डरिंग के मामले में ईडी अब

- **ईडी चार दिन में कोई खास बयान दर्ज नहीं कर सकी।**

आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल करने की तैयारी में है। रिमांड के दौरान पूछताछ से मिले जवाब और साक्ष्यों के आधार पर जांच को अंतिम रूप देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में मामले से संबंधित सुनवाई और संभावित आदेश को लेकर भी ईडी अपनी जांच से जुड़े तथ्य तैयार कर रही है। ईडी की जांच का प्रमुख केंद्र मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च हुई रकम और उसके स्रोत हैं। एजेंसी विश्वविद्यालय से जुड़ी जमीन और 59 भवनों की संपत्तियों को लेकर पहले ही 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर चुकी है।

दस साल में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हुआ

मुफ्त व सस्ती दवाओं, जांच और अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं से परिवारों पर सीधे खर्च का बोझ कम हुआ

नई दिल्ली, 15 नवंबर। देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च पिछले दस वर्षों में तीन गुना से अधिक बढ़ कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, कुल स्वास्थ्य खर्च में परिवारों की जेब से होने वाले सीधे खर्च की हिस्सेदारी 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2023-24 के अनुसार, इस अवधि में परिवारों के सीधे स्वास्थ्य खर्च की हिस्सेदारी में 21.5 प्रतिशत अंक की कमी आई है।

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2023-24 के अनुसार कुल स्वास्थ्य खर्च में परिवारों की जेब से होने वाले सीधे खर्च की हिस्सेदारी दस वर्ष में 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गई।**

परिवारों की जेब से होने वाला स्वास्थ्य खर्च 2013-14 में कुल स्वास्थ्य खर्च का 64.2 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 में यह घटकर 43.4 प्रतिशत और 2023-24 में 42.7 प्रतिशत रह गया। मंत्रालय के अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और मुफ्त या सस्ती दवाओं, जांच तथा अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं से परिवारों पर सीधे खर्च का बोझ कम करने में मदद मिली है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च भी बढ़ कर 1.53 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। इसके तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन केंद्रों पर गैर-संचारी रोगों की जांच, आवश्यक दवाएं, जांच सुविधाएं और बीमारी से बचाव से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा खर्च की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। कुल स्वास्थ्य खर्च में इसकी हिस्सेदारी 2013-14 के छह प्रतिशत से बढ़ कर 2023-24 में 11 प्रतिशत हो गई है। इसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राज्यों की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा खर्च शामिल हैं। इसी अवधि में निजी स्वास्थ्य बीमा खर्च की हिस्सेदारी भी 3.4 प्रतिशत से बढ़ कर 10.2 प्रतिशत हो गई है। मंत्रालय के अनुसार, यह देश में स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ ने का संकेत है।

इज़रायल के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गया। इसमें कहा गया है कि वह हमास को मजबूत करने और आतंकी हमलों को आगे बढ़ ाने और उन्हें अंजाम देने की योजनाएं बनाने का काम कर रहा था। दो महीने पहले, उससे पहले इस पद पर रहे व्यक्ति को भी इज़रायल ने मार दिया गया था।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908